आईएमएफ बेलआउट्स

द हिन्दू

पेपर-II
(अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पिछले सप्ताह श्रीलंका की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के लिए $3 बिलियन बेलआउट योजना की पुष्टि की। आईएमएफ के अधिकारी भी पाकिस्तान के साथ $1.1 बिलियन की बेलआउट योजना के लिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि देश गिरती मुद्रा और मूल्य वृद्धि से चिह्नित एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।

राष्ट्र आईएमएफ बेलआउट की माँग क्यों करते हैं?

देश आमतौर पर आईएमएफ से मदद माँगते हैं जब उनकी अर्थव्यवस्थाओं को एक प्रमुख व्यापक आर्थिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, ज्यादातर मुद्रा संकट के रूप में। उदाहरण के लिए, श्रीलंका और पाकिस्तान के मामले में, दोनों देशों ने घरेलू कीमतों में तेजी से वृद्धि देखी है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले उनकी मुद्राओं का विनिमय मूल्य तेजी से गिरा है। इस तरह के मुद्रा संकट आमतौर पर सत्तारूढ़ सरकार के गुप्त प्रभाव के तहत अक्सर अपने केंद्रीय बैंक द्वारा देश की मुद्रा के सकल कुप्रबंधन का परिणाम होते हैं। लोकलुभावन खर्चों को निधि देने के लिए केंद्रीय बैंकों को सरकारों द्वारा मजबूर किया जा सकता है। इस तरह के खर्च

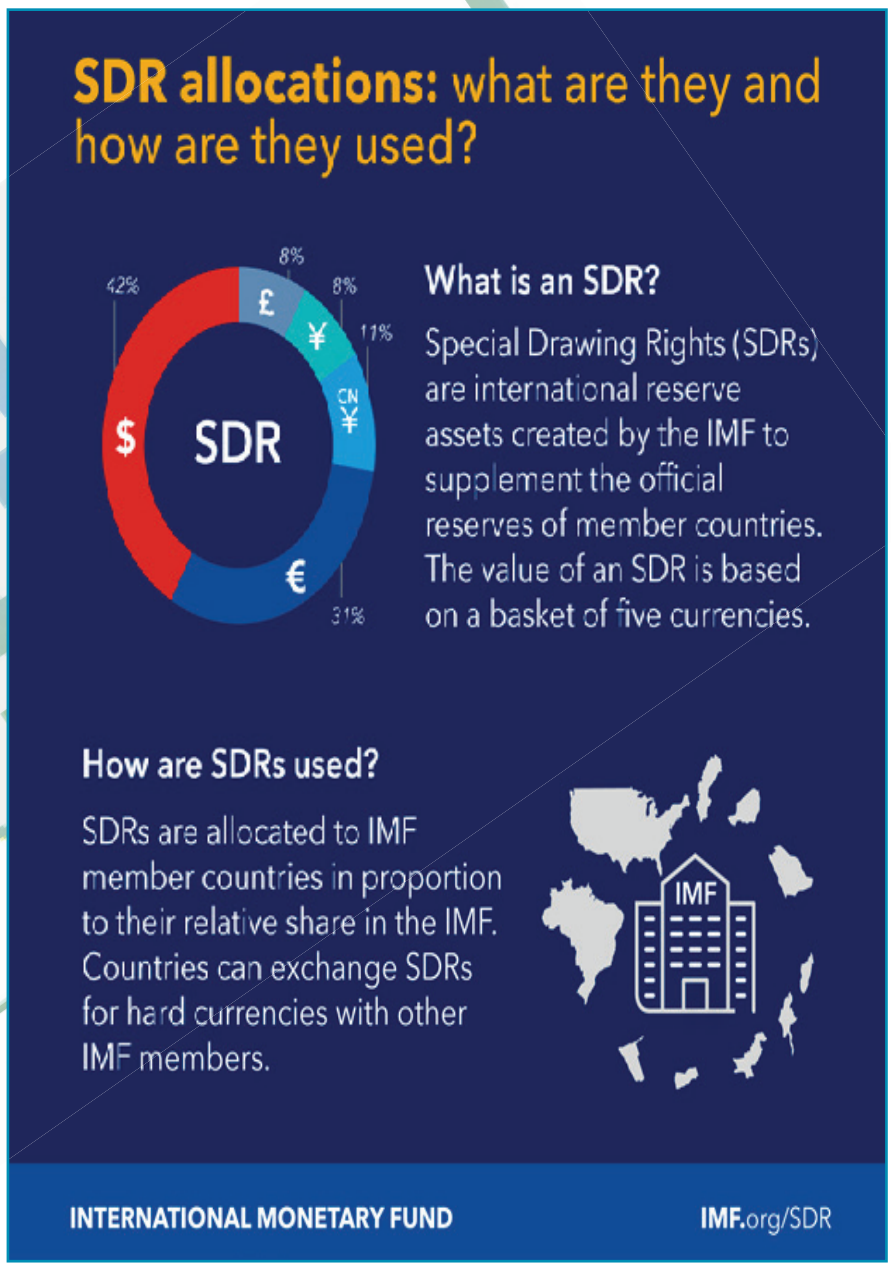

के परिणामस्वरूप अंततः समग्र धन आपूर्ति में तेजी से वृद्धि होती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि होती है और मुद्रा का विनिमय मूल्य गिर जाता है।

मुद्रा अवमूल्यन और मूल्य वृद्धि अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है?

मुद्रा के मूल्य में तेजी से, अप्रत्याशित गिरावट उक्त मुद्रा में विश्वास को नष्ट कर सकती है और आर्थिक गतिविधि को प्रभावित कर सकती है क्योंकि लोग वस्तुओं और सेवाओं के बदले मुद्रा को स्वीकार करने में संकोच कर सकते हैं। विदेशी भी ऐसी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं जहाँ इसकी मुद्रा का मूल्य अप्रत्याशित तरीके से बढ़ता है। ऐसे परिदृश्य में, कई देशों को अपने बाहरी ऋण और अन्य दायित्वों को पूरा करने, आवश्यक आयात खरीदने और अपनी मुद्राओं के विनिमय मूल्य को बढ़ाने के लिए आईएमएफ से मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

इस बीच, किसी देश की घरेलू आर्थिक नीतियों का उसकी मुद्रा की विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, आर्थिक नीति जो उत्पादकता को खतरे में डालती है, अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने की देश की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। दुर्भाग्य भी संकट में योगदान दे सकता है। श्रीलंका के मामले में देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कमी के कारण राष्ट्र में अमेरिकी डॉलर के प्रवाह में भारी गिरावट आई।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद युद्ध में तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये विश्व बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान इन दोनों संगठनों की स्थापना पर सहमति बनी। इसलिये इन्हें ब्रेटन वुड्स के जुड़वाँ संतानों यानी ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के रूप में भी जाना जाता है। आईएमएफ की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी, यह उन 190 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है जो इसके वैश्विक सदस्य हैं।आईएमएफ दिसंबर 1945 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया।
- आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है, यह विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली है जो देशों (और उनके नागरिकों) को एक-दूसरे के साथ लेनदेन करने में सक्षम बनाती है। आईएमएफ द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता हैं।

भारत और आईएमएफ

- भारत ने 27 दिसंबर, 1945 को आईएमएफ की सदस्यता ग्रहण की।1993 के बाद से, भारत ने आईएमएफ से वित्तीय मदद का अनुरोध नहीं किया है। वित्त मंत्री आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पदेन गवर्नर के रूप में कार्य करता है। हाल ही में, भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नवंबर 2022 में IMF के कार्यकारी निदेशक (भारत) के पद पर नियुक्त किया गया है।
- भारत का वर्तमान आईएमएफ कोटा SDR (विशेष आहरण अधिकार) 5,821.5 मिलियन है, जो इसे कोटा रखने वाले देशों में 13वें स्थान पर रखता है और इसे 2.44% हिस्सेदारी प्रदान करता है। हालाँकि, वोटिंग शेयर के मामले में, भारत (अपने निर्वाचन क्षेत्र के देशों बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ) कार्यकारी बोर्ड में 24 में से 17वें स्थान पर है।

कार्य

विनियामक कार्य: आईएमएफ एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है और समझौते के लेखों के नियमों के अनुसार, यह विनिमय दर नीतियों के लिए एक आचार संहिता और चालू खाता लेनदेन के लिए भुगतान पर प्रतिबंध लगाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

वित्तीय कार्य: आईएमएफ अल्पावधि और मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन (बीओपी) असमानता को पूरा करने के लिए सदस्य देशों को वित्तीय सहायता और संसाधन प्रदान करता है।

परामर्शी कार्य: आईएमएफ सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक केंद्र है। यह सलाह और तकनीकी सहायता के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है।

आईएमएफ देशों की मदद कैसे करता है?

आईएमएफ मूल रूप से विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) के रूप में, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को ऋण देता है जो ऋणदाता की सहायता चाहते हैं। एसडीआर केवल पाँच मुद्राओं की एक टोकरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात् यू.एस. डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। आईएमएफ विस्तारित क्रेडिट सुविधा, लचीली क्रेडिट लाइन, स्टैंडबाय समझौते आदि जैसे कई ऋण कार्यक्रमों के माध्यम से संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को अपना ऋण देता है। बेलआउट प्राप्त करने वाले देश अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए एसडीआर का उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में, श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों को आवश्यक वस्तुओं के आयात और अपने विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए अमेरिकी डॉलर की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए उन्हें आईएमएफ से मिलने वाला कोई भी पैसा इन जरूरी मुद्दों को हल करने की दिशा में जाने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

आईएमएफ की स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। उस समय आईएमएफ का प्राथमिक लक्ष्य अपने स्वयं के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे देशों द्वारा प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समन्वय लाना था। अंततः आईएमएफ उन देशों की सरकारों के लिए अंतिम उपाय का ऋणदाता बन गया, जिन्हें गंभीर मुद्रा संकट से निपटना पड़ा।

क्या आईएमएफ बेलआउट से जुड़ी कोई शर्त है?

आईएमएफ आमतौर पर देशों को पैसा उधार देने से पहले उन पर शर्तें लगाता है। उदाहरण के लिए, किसी देश को आईएमएफ ऋण प्राप्त करने की शर्त के रूप में कुछ संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिए सहमत होना पड़ सकता है। आईएमएफ का सशर्त उधार विवादास्पद रहा है क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये सुधार जनता के लिए बहुत कठिन है। कुछ ने आईएमएफ के ऋण देने के फैसलों पर भी आरोप लगाया है, जो विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित होने के लिए जाते हैं। हालांकि, आईएमएफ की उधार नीतियों के समर्थकों ने तर्क दिया है कि आईएमएफ ऋण देने की सफलता के लिए शर्तें आवश्यक है।

एक देश के लिए जो आईएमएफ बेलआउट चाहते हैं, आमतौर पर उनकी सरकारों द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियों के कारण संकट में हैं, जो आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए प्रतिकूल साबित हुई हैं। इस प्रकार आईएमएफ के लिए एक ऐसे देश पर पैसा फेंकना समझदारी नहीं हो सकती है, जब इसके संकट का कारण बनने वाली नीतियां अछूती रहती हैं। उदाहरण के लिए, आईएमएफ अपने केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्च मूल्य मुद्रास्फीति से प्रभावित देश की मांग कर सकता है। भ्रष्टाचार एक और मुद्दा है। संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को दिया जाने वाला आईएमएफ का ऋण व्यर्थ प्रयास साबित हो सकता है क्योंकि इन अर्थव्यवस्थाओं में खराब संस्थान हैं और उच्च स्तर से पीड़ित हैं।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : "रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट" और "रैपिड क्रेडिट सुविधा" निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार देने के प्रावधानों से संबंधित हैं?

(a) एशियाई विकास बैंक

(b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(c) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल

(d) विश्व बैंक

Que. "Rapid Financing Instrument" and "Rapid Credit Facility" are related to the provision of lending by which of the following?

(a) Asian Development Bank

(b) International Monetary Fund

(c) United Nations Environment Program Finance Initiative

(d) World Bank

उत्तर : B

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : कुछ अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों के पास आर्थिक भागीदारी के लिए विशेष शर्तें हैं, जो प्रमुख देशों से सोर्सिंग उपकरण के लिए उपयोग की जाने वाली सहायता के पर्याप्त घटक को निर्धारित करती हैं। ऐसी शर्तों के गुणों का उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- आईएमएफ के बारे में तथा इसके द्वारा दिए जाने वाले मदद संबंधी शर्तों को समझाएं।
- सोर्सिंग उपकरण के लिए उपयोग की जाने वाले घटकों के बारे में बताएं।
- हाल के उदाहरण को देते हुए स्पष्ट कीजिए।
- संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।